

अपीलाए ने यह अपील विज्ञान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, अक्षिया द्वारा राखव वाद संख्या 22/2019 महेंद्र कुमार बलाम परेश इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 14 अगस्त 2019 के खिलाफ राखव स्थान काराकारी अखिलियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत अदालत

द्वारा के समक्ष दिनांक 01 अक्टूबर 2019 को प्रस्तुत की है।

इस प्रकार के साक्ष्य तथ्य इस प्रकार है कि अखिलियम ज्योत्सना के समक्ष वादी-अपीलाए ने राखव स्थान काराकारी अखिलियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत एक राखव वाद आम बैठक/अक्षिया के राखव संख्या 370 रकबा 72 बीघा 05 बिस्वा के एक-तिहाई हिस्से की भूमि बाबत

खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्ली घात करने हेतु प्रस्तुत किया। उक्त वाद विचाराधीन रहने के दौरान दिनांक 09 जुलाई 2019 को प्रतिवादीवाए की ओर से एक पारदर्शक अन्तर्गत आदेश 07

दिनांक 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया, जो अखिलियम ज्योत्सना द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2019 को स्वीकार किया जाकर वादीवाए-अपीलाए के दावा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से

खिलाफ़ा इकर वादीवाए-अपीलाए ने राखव स्थान काराकारी अखिलियम, 1955 की धारा 223 के तहत आखिलियम अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विज्ञान अखिलियमवाए की बहस सुनी गयी। विज्ञान अखिलियमवा अपीलाए ने तथ्यों एवं अपील भीमों में पारित निर्णयों को दोहराते हुए कथन किया कि आम बैठक/अक्षिया के राखव संख्या 370 रकबा 72 बीघा 05 बिस्वा के एक-तिहाई हिस्से के खातेदार मोहनलाल, प्रभाराम, कन्हैयालाल प्रसन्न गुण्डीवाल सोनार द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का

बेदान वादी एवं उसके भाई लाला कुमार के पक्ष में दिनांक 24 नवम्बर 1985 को नरिये पनीबखु विकस्य विवेख के माध्यम से किया जाना, बेदान के बाद उक्त विकस्यवाए का विकस्यवा भूमि में कोई स्वतन्त्र एवं अधिकार

MAHENDRA KUMARA VS PARASH ETC
 1955
 22/2019



होता है, प्रतिवादी-पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं बचाव बिडुआ

बाबत किसी प्रकार से जोर नहीं किया जा सकता। मगर अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अस्थायी बिषयाज्ञापन के प्रावधानों को

आधार बना कर वादी को वाद खारिज करने में बिधिक भंग की है।

अधिवक्ता-अपीलेंट का यह भी कथन है कि प्रतिवादी संख्या दो को

प्रावधान अन्वयेत आदेश 07 दिनांक 11 सीपीसी पेश करने को बिधिक

अधिकार ही उपलब्ध नहीं था, क्योंकि प्रतिवादी संख्या दो स्वयं एक

अनर्ही व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को दावा आदेश 7

दिनांक 11 सीपीसी के प्रावधानों के आधार पर खारिज कर दिया मगर

इसकी पूर्ति बनाये जाने के आदेश पारित नहीं किये गये, इस कारण

अपील के साथ इसकी पूर्ति की नकल पेश नहीं की जा सकी है। अब मैं

अधिवक्ता अपीलेंट को अधीन स्वीकार की जाकर बाँझव अर्जा पेश

किये जाने का निवेदन किया।

जबकि मैं अधिवक्ता सेन्थी, ने कथन किया कि न्यायालय सहायक

कलेक्टर एवं उपरत अधिकारी आदिवासी के समाक्ष वादी-अपीलेंट ने

वादावत आराजी के संबंध में पूर्व में 13 अप्रैल 2011 को एक दावा

73/2011 महेंद्रकुमार व अन्य बनाम प्रमोद इत्यादि पेश किया था, जो

दिनांक 08 जुलाई 2016 को बिस्तारित किया गया। इसके बाद पूर्व:

वादी-अपीलेंट ने पूर्ववर्ती वाद के खसाम को ही नये वाद के रूप में

दिनांक 01 अक्टूबर 2019 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर स्थान आदेश

प्राप्त कर लिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में इस दावा को

बाबत स्थान प्रावधानों के बिना किये जाने पर कस पूकार पेशवावती

प्रकरण द्वारा बिधिक द्वारा बिधिक प्रमाणों के बिना ही इस

प्रकरण-योजना को ही मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

बिधिकारण: पारित किया गया है। पूर्ववर्ती प्रावधानों के साथ संलग्न

Handwritten signature and stamp at the top of the page.



विधिवत विभाजन कस्ये बेचान किया है, अतः नया वाद प्रस्तुत करना पडा है। किन्तु नया वाद प्रेष करने का यह कारण मान्य नहीं है और न ही वादी-अपीलापट को जो नवीन वादकल्प उत्पन्न हुआ है, उसका समाधान है। यदि किसी वाद के दौरान वादग्रस्त सम्पत्ति/आसनों का प्रदीय पक्ष को बेचान कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि कंवा को विचारणीय वाद में नियमानुसार न्यायालय में आवेदन प्रेष कर पक्षकार कायम करना लिया जावे। नया वाद प्रेष करना कोई अर्जा नहीं है। अपील स्तर पर अधिवक्ता अपीलापट अपीलाणील आदेश में ऐसी कोई सार्वगत भी अधवा अनियमितता इतिहा नहीं कर पाये जिसके आधार पर अपीलाणील विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाने का कोई औचित्य या आवश्यकता प्रतीत हो।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलापटसु स्वीकार किया जाने योग्य नहीं जाती है, जो तदनुसार खतिन की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाणील विषय दिनांक 14 अगस्त 2019 यथावत रखा जाता है। इस विषय का कोई प्रतिकूल प्रभाव पूर्व में चल रहे वाद संख्या 73/2011 महेंद्रकुमार वीरेंद्र वनाम प्रेमराज वीरेंद्र की किसी भी कार्यवाही पर नहीं रहेगा। खासा पक्षकारानु अफगल-अफगल बहन करे। इसकी पूर्वा जारी किया जावे।

22/11/2020

विषय खर्चे न्यायालय में सुनाना गया।
 (नयावतल वादकद)
 राजेंद्र अपील पक्षिकारी, जीहापुर



१५५३
 भारतीय न्याय प्रणाली

यह अधीन बारीख 22 जनवरी 2020 खरब बहानरी अधिवरता श्री खयाराम वीधरी भिजवाविष अधीगाएए एव श्री रजेश रवीवड भिजवाविष रेएरी. एव श्री ईदाराम वीधरी राजकीय अधिवरता भिजवाविष रेएरी. सख्या सात समायत पेश होकर हुकम हुआ कि समस्त विवेक के आधार पर अधीन अधीगाएएए सरीकार किसे जाले योज्य नही पायी जाती है, जो तदनुसार खरिज की जाती है तथा अधीनस्थ

----- 0 -----

अधीन अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान कायदकारी
 अधिवरता, 1955 विरुद्ध विरुद्ध सहायक कलेक्टर
 अधिसूचा दिनांक 14 अक्टूबर 2019 राजस्व बांटे सख्या
 22/2019 महत्व कृमार बलाम परेश इत्यादि

१. परेश एव श्री भिखीगाल महल, विवासी बाम बेववासिया, तहसील अधिसूचा, जिला जोधपुर
२. पर्याप्त एव डाकूम बाम, विवासी पण्डव जी की डणी, तहसील अधिसूचा, जिला जोधपुर के
३. हीरागाल एव एव पुत्र पुत्रीगाल कायमकामान--
४. अ. राजम एव क. हीरागाल
५. पुत्रगाल एव पुत्रीगाल
६. कन्हैयागाल एव पुत्र पुत्रीगाल
- समस्त जिला अधिसूचा, जिला जोधपुर विवासीगाल बाम पण्डव जी की डणी
७. तहसील अधिसूचा, जिला जोधपुर



अ
 वा
 ब

अधीन
 महत्वकृमार एव पुत्रगाल
 अधिवरता देशलहरा
 विवासी बाम बेववासिया
 पण्डव जी की डणी
 तहसील अधिसूचा, जिला
 जोधपुर

डिप्टी वरीव अधीन
 अब अदालत राजस्व अधीन पाधिकारी, जोधपुर
 बडनगाल पीठाधीन अधिकारी श्री नखतगाल बरडव, आ.प.प.स.

